उ.प्र. में औद्योगिक भूखण्डों को फ्री–होल्ड करने का निर्णय विचाराधीन

जनवरी 2015 तक कारोबार करने की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां (Doing business best practices) लागू हो जाएंगीः प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास

यूपीएसआईडीसी द्वारा मेरठ व सहारनपुर में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना

लखनऊ/मेरठ, 31 अक्टूबर 2014:

''राज्य सरकार औद्योगिक भूखण्डों को फ्री–होल्ड करने के निर्णय पर गम्भीरता से विचार कर रही है। लम्बे समय से उद्योगों की यह मांग रही है, किन्तु क्योंकि इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे अतः कई पक्षों पर विचारोपरान्त ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,'' **प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, श्री संचीव सरन ने कहा।** यह विचार उन्होंने **वेस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उ.प्र. द्वारा आज मेरठ में आयोजित शासन व उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम में कही।**

श्री सरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत् है, जिसके लिए अनेक नवीन कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार का यह उद्येश्य है कि उद्योगों के संचालन व स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए, जिसके लिए साप्ताहिक 'औद्योगिक समाधान दिवस', ऑनलाइन औद्योगिक शिकायत निवारण प्रणाली तथा दूरभाष की हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिससे उद्यमी व उद्योग आसानी से अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकें।

प्रदेश में कारोबार, उद्यम व उद्योग के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के विषय में **प्रमुख सचिव ने बताया** कि सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव औद्योगिक संगठनों से इस विषय पर विचार–विमर्श कर प्रणालियों को सरल व बेहतर बनाने के लिए अपने प्रस्ताव मुख्य सचिव के समक्ष नवम्बर माह के अन्त तक प्रस्तुत करेंगे। जनवरी 2015 तक कारोबार करने की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां (Doing business best practices) लागू होने की सम्भावना है।

इसके पूर्व अपने स्वागत भाषण में **वेस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डा0 बृज भूषण** ने उद्यम व उद्योग के प्रति राज्य सरकार के सकारात्मक रूख की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ बिन्दु हैं जिन पर तुरन्त ध्यान देने की अवश्यकता है, जैसे– प्रदूषण से संबंधित अनापत्ति, लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यमों के लिए विद्युत ड्यूटी से छूट, तथा उद्यमियों की समस्याओं के निवारण का सघन अनुश्रवण।

वेस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की औद्योगिक विकास काउंसिल के अध्यक्ष **राम कुमार गुप्ता** ने औद्योगिक भूखण्डों को फ्री–होल्ड करने, खेल–कूद के उत्पादों के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा लकड़ी पर रोक लगाने के फलस्वरूप लकड़ी की उपलब्धता, विष्वस्तर पर चमड़ा उद्योग में बने रहने के लिए अच्छे चमड़े की उपलब्धता तथा एमएसएमई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों में प्रतिभाग करने हेतु सहायता आदि मुद्दों को उठाया।

यूपीएसआईडीसी के प्रबन्ध निदेशक, श्री मनोज सिंह ने बताया कि भूमि उपलब्ध होने पर निगम द्वारा मेरठ व सहारनपुर में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि भूमि ट्रांसफर लेवी के मुद्दे का भी शीघ्र ही समाधान हो जाएगा।

सूचित किया गया कि प्रदेश के इस क्षे से लगभग 600 करोड़ रुपये का सालाना निर्यात होता है जिसमें से लगभग 300 करोड़ रुपये का निर्यात खेलकूद के उत्पादों का होता है। इसमें क्रिकेट बैट के अलावा एथलेटिक्स व टेनिस तथा अन्य खेलों के उत्पाद भी निर्यात किये जाते हैं जिन्होंने विश्व में लोकप्रयता अर्जित की है।

सम्मेलन में 200 से अधिक उद्यमियों व उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को फेडरेशन ऑफ यू.पी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन, परतापुर इण्डस्ट्रियल इस्टेट मैन्यूफैक्चरर्स, ऑल इण्डिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्यूफैक्चरर्स, तथा इण्डस्ट्रियल एरिया मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन गाज़ियाबाद ने **सह–प्रायोजित** किया था।

आयुक्त एवं निदेशक–उद्योग, श्री एल वेंकटेश्वर लू, विशेष सचिव औद्योगिक विकास–सुश्री कंचन वर्मा, मेरठ व मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी– श्री पंकज यादव व श्री कौशलराज शर्मा सहित कई विभागों के अधिरियों ने प्रतिभाग किया।